



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 25 फरवरी, 2005/6 फाल्गुन, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-9, 16 फरवरी, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एच०ए०(5) 102/2004-3050-56.—यह कि श्री सुरेन्द्र पाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर एवं अन्य वार्ड पंचों से प्राप्त शिकायत पत्र पर प्रारम्भिक छानबीन उप-निदेशक एवं उप-सचिव (पंचायत), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई। जिसके फलस्वरूप आप राजीव आवास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु श्रीमती मान देई पत्नी श्री अनन्त राम को मु० 18000/- रु० की राशि गलत प्रमाण-पत्र देकर लाभार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने की दोषी पाई गई है;

अतः यह कि मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत उपायुक्त, बिलासपुर द्वारा उनके कार्यालय के पत्र संख्या बी० एल० पी०-पंच 5321-25, दिनांक 26-10-2004 द्वारा नियमित जांच जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सौंपी गई।

अतः यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, बिलासपुर से उनके कार्यालय पत्र संख्या बी० एल० पी०-पंच 5933, दिनांक 3-1-2005 के अन्तर्गत निदेशालय में प्राप्त हुई तथा रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने के उपरान्त सरकार के ध्यान में आया है कि आप द्वारा बहसियत प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर, विकास खण्ड अण्डूता, जिला बिलासपुर श्रीमती मान देई पत्नी श्री अनन्त राम को राजीव आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि मु० 22,000/- रु० में से मु० 6000/- रु०

प्रथम किश्त तथा मु० 12,000/- रु० द्वितीय किश्त मौके पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किए बगैर जारी कर लाभार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाकर कुल मु० 18,000/- रु० की राशि का दुरुपयोग किया है। लाभार्थी द्वारा भी उक्त राशि का प्रयोग अपने पुराने मकान की मरम्मत पर व्यय किया है। केवल शीचालय ही नया बनाया है। यदि यह मामला प्रकाश में नहीं आता तो आप द्वारा गलत प्रमाण-पत्र जारी करने की वजह से मु० 18,000/- रु० की सरकारी राशि का दुरुपयोग हो जाता। आपका यह कृत्य हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (बी) की परिधि में आता है तथा आप उपरोक्त दर्शाए गए कृत्यों के लिए दुराचार के दोषी पाई गई हैं। यद्यपि उपरोक्त राशि लाभार्थी द्वारा दिनांक 19-10-2004 रसीद संख्या 1927533 अनुसार खण्ड विकास अधिकारी, झण्डूता के कार्यालय में जमा कर दी गई है।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देश दिए जाते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिए आपको प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर के पद से निष्काशित किया जाए। आप उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें। आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है।

पंजीकृत,

श्रीमती सुरेश कुमारी,

प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर, विकास खण्ड झण्डूता,
जिला बिलासपुर (हि० प्र)।

शिमला-171009, 16 फरवरी, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) रे-3031-36.—यह कि उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने उनके कार्यालय पत्र संख्या पंच-के० जी० आर०-57/2001-10876, दिनांक 1-2-2005 के अनुसार सूचित किया है कि आप द्वारा सरकारी भूमि खसरा नम्बर 572 एवं 782 पर सालम कब्जा होने वाले श्री मुभाष चन्द सपुत श्री भरुना राम, निवासी रे, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा के शिक्षायात पत्र पर तहसीलदार फतेहपुर से जांच करवाई गई थी। तहसीलदार फतेहपुर ने अपनी रिपोर्ट में उपरोक्त सरकारी भूमि पर आप द्वारा कब्जे की पुष्टि की है। परन्तु दिसम्बर 2000 में उप-प्रधान ग्राम पंचायत रे के पद पर चुनाव हेतु नामांकन पत्र में आपने घोषणा की है कि आप द्वारा किसी भी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अतः आपने उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व (ड) के अन्तर्गत स्वयं अयोग्यता अर्जित की है;

यह कि आप द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण तथा मिथ्या घोषणा कर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) व (ड) के अन्तर्गत अयोग्यता अर्जित करने के फलस्वरूप आपको हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (क) के अन्तर्गत उप-प्रधान पद से निष्काशित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से आपको निर्देश दिए जाते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिए आपको उप-प्रधान, ग्राम पंचायत रे के पद से निष्काशित किया जाए। आप उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें। आपका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तथा मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

सचिव (पंचायती राज)।

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th February, 2005

No. PCH HB(15) 6/2001-4366-4616.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to confer Gazetted Class-I Status upon District Panchayat Officer and Principals, Panchayati Raj Training Institute (Presently Gazetted Class-II), in Himachal Pradesh with immediate effect.

Sd/-
Secretary.

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th February, 2005

No. SJE-A(4)-1/2004.—In continuation to this department notifications of even No. dated 4-2-2004, 10-2-2004, 25-2-2004, 3-5-2004, 11-8-2004, 18-8-2004, 24-8-2004, 17-9-2004 and 17-12-2004, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate Sh. Lal Chand Sanotia s/c Sh. Jagat Ram, r/o Sanot, P. O. Dehra, District Kangra (H. P.) as non-official member of the H. P. Scheduled Castes Welfare Board.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

